

मुख्य समाचार :-

- राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज, 17 हजार 829 प्रत्याशियों का भाग्य होगा तय।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अभियोजन की अनुमति दी।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन हिस्सेदारी के रूप में उत्तराखंड को एक हजार छह सौ करोड़ रुपये की धनराशि दी।
- देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला के शहरी क्षेत्रों में जल निकासी के समाधान के लिये जिला प्रशासन ने 17 डी-वाटरिंग पंप खरीदे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस चरण में राज्य के 12 जिलों के 49 विकासखंडों में वोटिंग होगी। लगभग 26 लाख मतदाता 17 हजार 829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां कल देर शाम तक अपने गंतव्यों पर पहुंच गई हैं और मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। इस बार पंचायत चुनाव दो चरणों में कराया जा रहा है। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 31 जुलाई को कराई जाएगी। पूरे चुनाव में मतपत्र के जरिए मतदान कराया जा रहा है। उधर, पिथौरागढ़ जिले की भड़गांव जिला पंचायत सीट पर मतदान पर रोक लगा दी गई है। यह रोक उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लगाई गई है।

अपील

इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें, ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं और इन चुनावों में सभी मतदाताओं की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से विशेष रूप से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वोट राज्य के भविष्य को गढ़ने में निर्णायक भूमिका निभाता है और लोकतंत्र की मजबूती मतदाता की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है।

स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अभियोजन की अनुमति दी है। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिप्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामलों को सीबीआई को सौंपने की स्वीकृति दी गई है। पाखरों टाइगर सफारी निर्माण में अनियमितताओं को लेकर दो पूर्व वन अधिकारियों— अखिलेश तिवारी और किशन चंद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई है। इस बीच, मुख्यमंत्री ने मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त पुलों के लिये बैली ब्रिजों की आपूर्ति के लिए 27 करोड़ रुपये और नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग के दो कार्यों के लिए करीब पांच करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा कई विकास योजनाओं के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है, जिनमें चौबट्टाखाल, हरिद्वार, भीमताल, कर्णप्रयाग और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य शामिल हैं। देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में इस्कॉन मार्ग के चौड़ीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

बकाया धनराशि

राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ना किसानों की बकाया राशि जारी कर दी है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि चीनी मिल डोईवाला के लिए 22 करोड़ 47 लाख और बाजपुर चीनी मिल के लिए 25 करोड़ नौ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। श्री बहुगुणा ने बताया कि इससे पहले सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए 92 करोड़ चौदह लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इस तरह पेराई सत्र 2024-25 के लिए अब तक कुल 139 करोड़ रुपये गन्ना किसानों के भुगतान के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा फार्मास्युटिकल पैकेजिंग के मानकों पर केंद्रित 'मानक मंथन' कार्यक्रम का आयोजन यूकॉस्ट, देहरादून में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औषधीय पैकेजिंग के लिये एल्युमिनियम फॉइल से जुड़े बी.आई.एस मानक की समीक्षा और हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना था। कार्यक्रम में फार्मा उद्योग, तकनीकी विशेषज्ञों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बी.आई.एस निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सीधे पैकेजिंग मानकों से जुड़ी होती है, इसलिए इन मानकों को व्यावहारिक और अद्यतन बनाए रखना आवश्यक है। तकनीकी सत्र का संचालन वैज्ञानिक सचिन चौधरी ने किया और उन्होंने तकनीकी पहलुओं, निर्माण मानकों, परीक्षण विधियों और वैश्विक रुझानों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों ने फार्मा पैकेजिंग की गुणवत्ता और मानकों के संशोधन से जुड़े विषयों पर सक्रिय चर्चा की।

धनराशि

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन हिस्सेदारी के रूप में उत्तराखंड को एक हजार छह सौ करोड़ रुपये की धनराशि दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पेंशन व्यय को लेकर उत्तर प्रदेश पर कुल 2 हजार 261 करोड़ रुपये की देनदारी थी। इसमें से सोलह सौ करोड़ रुपये की पहली किस्त जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को भेज दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग और संवाद की सकारात्मक भावना से वर्षों से लंबित परिसंपत्तियों और दायित्वों से जुड़े मुद्दों का समाधान तेजी से हो रहा है।

जल निकासी प्रबंधन

देहरादून शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार की है। आईएसबीटी क्षेत्र में जल निकासी के स्थायी समाधान के बाद अब देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला के शहरी क्षेत्रों में जल निकासी को लेकर 17 डी-वाटरिंग पंप खरीदे गए हैं, जिन्हें संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां डी-वाटरिंग पंप लगाए जाएंगे। नगर निगम देहरादून, जल संस्थान और जल निगम को 10, नगर निगम ऋषिकेश को 4, डोईवाला को 2 और तहसील ऋषिकेश को 1 पंप, मड पंप सहित प्रदान किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया टीम भी तैनात की है। ये टीम नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरी और कुमकुम जोशी के नेतृत्व में कार्य करेंगी और चोकिंग या जल निकासी में किसी भी रुकावट पर तुरंत कार्रवाई करेंगी।

कांवड़ मेला

शिव चतुर्दशी के दिन भगवान शिव के जलामिषेक के साथ कल श्रावण मास का कांवड़ मेला सम्पन्न हो गया। 13 दिन चले इस मेले में हरिद्वार से करीब 4 करोड़ 53 लाख कांवड़ियों ने गंगाजल भरकर अपने-अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान किया। मेले की शुरुआत से लेकर कल शाम तक हर की पैड़ी और आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। बीते चार दिनों से हरिद्वार पूरी तरह भोलेनाथ के जयघोषों से गूंजता रहा, लेकिन बुधवार शाम को मेले के समापन के साथ ही शहर में शांत वातावरण हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि मेला निर्विघ्न संपन्न हुआ। गंगा में डूबते हुए 183 कांवड़ियों में से 170 को एसडीआरएफ, पीएसी और सेना की टीमों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि 4 की डूबने से मौत हो गई और 9 श्रद्धालु अब भी लापता हैं। पुलिस ने बड़ी संख्या में खोए हुए लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया।

रात्रि यातायात पर रोक

अल्मोड़ा जिले में क्वारब पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने की वजह से यह मार्ग रात के समय यातायात के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर 18 अगस्त तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हल्के व भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन ही इस दौरान छूट में रहेंगे।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है— 55 साल के शिक्षक भी सीधी भर्ती में बन सकेंगे प्रधानाचार्य। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है— प्रधानाचार्य भर्ती में एलटी शिक्षक को भी मौका, आयु सीमा भी बढ़ाई। राष्ट्रीय सहारा लिखता है — अब प्रधानाचार्य बनने के लिए देनी होगी विभागीय परीक्षा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज प्रथम चरण के मतदान को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। नवोदय टाइम्स लिखता है — गांवों की सरकार के लिए प्रथम चरण का मतदान आज। दैनिक जागरण लिखता है — आज चुनी जाएगी गांव की सरकार।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में नए कुलपति की तैनाती की खबर को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है — प्रोफेसर लोहनी बने मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति।

